क्लासिफाइड

राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना तथा परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए: रामप्रताप

महानगर संवाददाता

जयपुर। जल संसाधन मंत्री डॉ. रामप्रताप ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना तथा परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सम्पन्न राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक में डॉ. रामप्रताप ने राजस्थान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दो को उठाया। डॉ. रामप्रताप ने बताया कि देश में कुल 16 परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जा चुका है। अतरू राजस्थान की ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना तथा परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का

दर्जा दिया जाना चाहिए ।उन्होंने बताया कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा यहां जल की अत्यधिक कमी है। देश के कुल सतही जल संसाधनो में से राज्य में मात्र 1.16 प्रतिशत सतही जल ही उपलब्ध है। डॉ. रामप्रताप ने अवगत कराया कि केन्द्र सरकार की नदी-जोड़ी परियोजना के अन्तर्गत शारदा नदी का अधिशेष जल साबरमती नदी तक अपवर्तित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि इस परियोजना की डी.पी.आर.शीघ्रताशीघ्र तैयार की जानी चाहिए तथा सर्वे एवं अनुसंधान के कार्य को प्राथमिकता से किया जाए ताकि परियोजना का लाभ राज्य को शीघ्र प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना के अन्तर्गत राज्य में बहने वाली नदियों के अधिशेष जल को शुष्क क्षेत्रें में अपवर्तित कर के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।उन्होंने इन्दिरा गांधी नहर फीडर की रिलाईनिंग के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र स्वीकृति हेतु निवेदन किया। रिलाईनिंग से जल की छीजत में कमी होगी तथा वाटर लोगिंग की समस्या से भी निजात मिलेगी। डॉ. रामप्रताप ने बताया कि भारत सरकार की वृहद परियोजना डी.एम.आई.सी. का लगभग 39 प्रतिशत हिस्सा राज्य में स्थित है।

हिंदी दिवस के उपलक्ष पर आज राष्ट्रपति प्रदान करेंगे पुरस्कार

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, की ओर से गुरुवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है ।

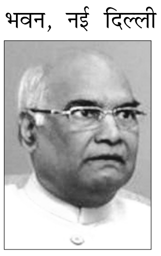

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में देश भर में स्थित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के प्रमुखों को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें शील्ड तथा प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। हिंदी दिवस पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

महानगर
की प्रति प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें।
(सुबह 10 से शाम 5 बजे)
मो. 8107288197

किराये के लिए

हीरापुरा बाईपास के पास सत्य कॉलोनी में पॉश

लोकेशन, 2 कमरे, लेटबाथ/किचन, बरामदा, बॉलकनी, अच्छी लोकेशन, शाकाहारी छात्रों के लिए किराये पर ग्राउंड फ्लोर में उपलब्ध है। सेपरेट एंट्रेंस।

संपर्क: 9413764079

राज कपूर से लेकर कुरोसावा तक की फिल्मों के 9200 प्रिंट गायब

विशेष संवाददाता

पुणे। पुणे स्थित नेशनल फिल्म आरकाइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई)से 92 हजार फिल्म प्रिंट के गायब होने का मामला सामने आया है। इनमें ख्यात भारतीय फिल्मकारों की और विदेशी फिल्में भी शामिल थीं। 2010 में नेशनल फिल्म आरकाइव ऑफ इंडिया ने पुणे की एक फर्म को अपनी सभी रील्स पर बारकोड लगाने की जिम्मेदारी दी थी। इस फर्म ने पाया कि हजारों रील्स ऑन रिकॉर्ड को मौजूद हैं, लेकिन ये फिजिकली ये कहीं नहीं हैं। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फिल्म रील्स के 51,500 डिब्बे और 92000 प्रिंट गायब हैं जबकि एनएफएआई अपने यहां 1.3

लाख फिल्म रील्स होने का दावा करता है। 4922 डिब्बों में 1112 फिल्म टाइटल मौजूद हैं, जो एनएफएआई के रजिस्टर में लिस्टेड नहीं हैं, लेकिन आरकाइव में मौजूद हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आरटीआई के जरिए पता चला है कि गायब होने वाले सेल्यूलॉइड प्रिंट्स में सत्यजीत रे (पाथेर पंचाली) , मेहबूब खान (मदर इंडिया), राज कपूर (मेरा नाम जोकर, अवारा), मृणाल सेन(भुवन शोम), गुरु दत्त (कागज के फूल) सहित कई फिल्मकारों की फिल्मों की प्रिंट शामिल हैं।

रेल यात्रा के लिए पहचान प्रमाणों में एम आधार को स्वीकृति

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। रेल मंत्रालय रेल यात्रा के लिए किसी भी सुरक्षित श्रेणी में निर्धारित पहचान प्रमाणों में एक पहचान के रूप में एम-आधार को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। एम-आधार यूआईडीएआई द्वारा लांच किया गया मोबाइल ऐप है। इसपर कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकता है। यह उसी मोबाइल नंबर से होगा जो आधार से जुड़ा है। आधार देखने के लिए व्यक्ति को अपना ऐप खोलना होगा और अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद स्क्रिन पर आए एम-आधार को भारतीय रेल की किसी भी आरक्षित श्रेणी में पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल ने 2017 का 'कंटेनर टर्मिनल ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी) को मुंबई में आयोजित गेटवे पुरस्कार 2017 में 0.6 मिलियन से अधिक टीईयू श्रेणी के लिए कंटेनर टर्मिनल ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जेएलएन पोर्ट के स्वामित्व वाले जेएनपीसीटी ने भीड़-भाड़ कम करने, कंटेनरों की सुचारू सुपुर्दगी और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच व्यापार को सहायता प्रदान करने, बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए अपनी सक्रिय रणनीतियों के लिए यह पुरस्कार जीता है। जेएनपीसीटी के उपाध्यक्ष नीरज बंसल ने कहा कि टर्मिनल पिछले कुछ सालों में विकास गति का सृजन करने में सफल हुआ है।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वाहन सं. आरजे-14-जीएच-1046, आरजे-14-जीएच-4988, आरजे-27-जीबी-0326 की फाइनेंस किश्तें नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी ने जब्त करके जिला परिवहन कार्यालय में अपने नाम करवाने हेतु आवेदन किया है। अगर वाहन स्वामी अथवा किसी को भी कोई आपति हो तो सात दिवस में कार्यालय प्रादेशिक परिवहन जगतपुरा में संपर्क करें।

पिता के निधन के 12 साल बाद उनका पिंडदान करने बनारस पहुंचे संजय दत्त

हिन्दू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष प्रप्ति के साथ उनका आशीर्वाद मिलता है, इसी कामना के साथ वाराणसी में फिल्म अभिनेता संजय दत्त अपने पूर्वजों का पिंडदान करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये उनके पिताजी की इच्छा थी। पुराणों में लिखा है कि काशी में जो मरता है उसे इस संसार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। जिसकी यहां मृत्यु नहीं होती लेकिन यदि उनका पिंडदान यहां किया जाता है तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी भावना लिए पितृपक्ष में लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की मुक्ति के लिए यहां आते हैं और गंगा पूजन कर उनके मोक्ष की मनोकामना करते हैं। गंगा तट पर किए गए श्राद्ध का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है।

पाठकगण ध्यान दें। किसी भी विज्ञापनदाता द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के दावे/प्रस्तुतिकरण के लिए जयपुर महानगर टाइम्स जिम्मेदार नहीं है। अत: किसी भी विज्ञापन पर कार्रवाई से पहले जरूरी/संपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

–प्रबंधक

कार्यालय नगर परिषद, दौसा (राजस्थान)

क्रमांक :- न.प.दौ./निविदा/2017-18/4217 दिनांक :- 11/09/2017

निविदा सूचना/2017-18

नगर परिषद दौसा द्वारा पंजीकृत संवेदकों व राज्य सरकार व उनके पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विवरण Website : www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।

निविदा सूचना की क्र.सं.	निविदा फार्म मिलने की तारीख	निविदा खोलने की तारीख
1 से 02	25/09/2017	25/09/2017

क्र.सं.	UBN No.
1	DLB1718WSRC09781
2	DLB1718WSRC09782

राज.संवाद/सी/17/3989 आयुक्त

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जारी

महानगर संवाददाता

अलवर। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से बुधवार को भी शहीद स्मारक पर सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं से विधायक शकुंतला रावत मिलीं। इस दौरान संघ की जिलाध्यक्ष लतेश शर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में महिलाओं ने विधायक को ज्ञापन सौंपकर सरकार से उनकी मांगें मनवाने का आग्रह किया। विधायक शकुंतला रावत ने आंदोलनकारी महिलाओं को आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत करवाएंगी। इसके अलावा यह मामला विधानसभा में भी उठाया जाएगा। नगर परिषद की पूर्व सभापति एवं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि अल्प मानदेय पर काम करने वाली महिलाएं लगातार 13 दिनों से अवकाश पर रह कर आम हड़ताल कर रही हैं जिससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से आम जनता को वंचित होना पड़ रहा है। इसके बावजूद झूठा वादा करने वाली भाजपा सरकार को ना तो आमजन के नुकसान की परवाह है , ना ही इन अल्प मानदेय वाली महिलाओं के अवकाश पर हड़ताल की चिंता है। संघ जिलाध्यक्ष लतेश शर्मा ने बताया कि हड़ताल के बावजूद सरकार हमारे नेताओं से वार्ता को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्वयं भाजपा घोषणा पत्र में हमें नियमित राज्य कर्मचारी बनाने का वादा किया और हमने भी महिला होने के कारण यह मान लिया कि महिला है महिलाओं का ज्यादा भला करेंगी।

भारत ने जाधव मामले में आईसीजे में लिखित दलीलें पेश की

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। भारत ने कुलभूषण जाधव के मामले में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आईसीजे में लिखित दलीलें पेश की। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के मामले में मृत्युदंड सुनाया था जिसके बाद भारत आईसीजे पहुंचा था। आईसीजे ने अपने अंतिम फैसले तक जाधव के मृत्युदंड पर रोक लगा दी थी। भारत ने मई में आईसीजे से जाधव की सजा पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत ने जाधव मामले में आईसीजे में लिखित दलीलें पेश कीं। ये पाकिस्तान की ओर से दूतावास संबंधित वियना संधि के उल्लंघन का मामला है। आज की हमारी लिखित दलीलें 8 मई 2017 को दायर किए गए आवेदन के संबंध में अगला कदम हैं। पाकिस्तान जाधव को पिछले साल मार्च में अशांत बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा करता है। इधर, भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया जहां उनके सेवानिवृत्ति के बाद अपने कानूनी कारोबारी हित हैं। आठ मई को भारत, कुलभूषण जाधव को हिरासत में रखने और मृत्युदंड सुनाए जाने के मामले में वियना संधि के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की मांग के साथ आईसीजे गया था।

कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों से हुई मारपीट में गिरफ्तारी की मांग

महानगर संवाददाता

अलवर। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में पार्षद कपिलराज शर्मा के अलावा अन्य आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं होने पर कर्मचारियों ने नाराजगी प्रकट की है। इस संबंध में राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने दोनों अधिकारियों से प्रकरण के अन्य आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष अरविंद यादव, मंत्री पंकज शर्मा सहित यशवंत मीणा, खेमचंद सैन, मुकुट बिहारी, तरुण शर्मा, आनंद शर्मा, मनोज मिश्रा, मनीष जैन, तेजसिंह सैनी व दुर्गेश चौला आदि शामिल थे।

वन्यजीव प्रेमियों ने सौंपा ज्ञापन

महानगर संवाददाता

अलवर। वन्य जीव प्रेमियों की ओर से बुधवार को जिला कलेक्टर राजन विशाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सरिस्का बाघ परियोजना के वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 7 मांगें शामिल हैं। सरिस्का क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध, वनकर्मियों की संख्या बढ़ाने व यहां संसाधनों की समुचित व्यवस्था करने की मांग शामिल है।

इसके अलावा जंगल क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाने एवं यहां होने वाली वन कटाई की रोकथाम लगाने तथा वन्य जीव अपराधों में सम्मिलित लोगों के सरिस्का क्षेत्र में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांगें भी शामिल है। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमी मौजूद रहे।